within 4.6 weeks of filing the application. State-wise data on foreign investment approved from 01.01.93 to 31.03.95 is given in the enclosed statement (*see* below). Statewise details of pending proposals are not centrally maintained.

Statement

Foreign Direct Investment approved (State-wise) for the period January 1993 to March 1995

State	Jan '93—Mar '95	
	Number	Investment (Rs. Million)
Maharashtra	367	54971.68
Others	425	49265.13
West Bengal	77	34499.42
Delhi	197	26789.58
Gujarat	104	18451.60
Tamil Nadu	203	17093.80
Andhra Pradesh	129	11238.23
Madhya Pradesh	42	9133.82
Orissa	18	8152.83
Karnataka	145	5927.72
Punjab	28	5012.80
Rajasthan	62	3627.71
Haryana	115	3394.48
Uttar Pradesh	79	2706.19
Pondicherry	17	1147.33
Goa	19	822.05
Chandigarh	10	723.62
Bihar	8	721.19
Dadra & Nagar Haveli	8	402.76
Kerala	21	354.34
Himachal Pradesh	10	139.65
Arunachal Pradesh	2	110.60
Daman & Diu	6	54.78
Andaman & Nicobar	5	9.84
Assam	3	9.24
Tripura	1	6.80
TOTAL:	2101	254767.19

विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु नियमों को सरल बनाना

4774 **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु राज्य सरकारों से नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से ही विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं सहित औद्योगिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए राज्य सरकारों से संपर्क बनाएं रखना एक सतत्

प्रक्रिया रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिंगल विंडो अनुमोदन प्रणाली, उन्नत आधारभूत सुविधाओं/सेल वाओं और स्वीकृति कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं को दूर करने पर बल दिया जाता है।

इस प्रकार के परस्पर संपर्क से अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित नीतिगत घोषणाएं, सिंगल विंडो अनुमोदन प्रणाली, निवेश प्रस्तावों की निगरानी के लिए सामान्य रूपरेखा और अनेक राज्यों में उच्च स्तरीय सुविधा समितियों का गठन हुआ है।

नेपा लिमिटेड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें:

4775. **श्री अजीत जोगी:**
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश की नेपा लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) शिकायतें मुख्यतः नेपा लिमिटेड के कार्यकलाप के बारे में है, जिनमें प्रबन्धन के विरुद्ध शिकायतें, कम्पनी द्वारा झेली जा रही समस्याएं कार्य निष्पादन और कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के बारे में शिकायतें शामिल हैं।

(ग) समय-समय पर प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है, कम्पनी से रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है तथा समुचित कार्रवाई की जाती है।

Letters written by M.P.s

4776. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the Members of Parliament to the Ministry of Industry during the period from 1st April, 1994 to 31st March, 1995 alongwith details thereof;

(b) what is the number of letters acknowledged out of them;

(c) what is the number of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) what is the break-up of final letters issued by the Ministry containing positive and negative replies respectively?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) A total of 1292 letters were written by Members of Parliament during the period 1st April, 1994 to 31st March, 1995. The details are as follows:—

1. Deptt. of IP&P and I.D.	612
2. BICP	002
3. DC(SST)	110
4. E.A. Office	005
5. Deptt. of Heavy Industry	555
6. Deptt. of P.E.	008
Total	1292

(b) 1260.

(c) 950.

(d) The suggestions contained in letters of Members of Parliament are given full consideration and replies sent to them according to the nature of suggestions and policy guidelines of the Government.

Industrial growth rate projections

4777. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial growth rate may surpass the eight per cent projected in the Economic Survey for 1994-95; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.